उर्वरक क्षेत्र में आय बढ़ाने के लिए कार्य-योजना

3063. श्रीमती चन्द्रिका अभिनन्दन जैन: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उर्वरक क्षेत्र में आय बढ़ाने और राजस्व की हानि को रोकने के लिए विपणन के नये तरीके अपनाकर प्रचालन-लागत और अन्य व्यय में कमी करने हेतु कोई कार्य-योजना बनायी है,

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कितनी सफलता मिली है,

(ग) क्या इस संबंध में किसी परामर्श दात्री संगठन के माध्यम से कोई सर्वेक्षण भी कराया गया है, और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फेलेरियो): (क) और (ख) उर्वरक कम्पनियों की विपणन रणनीति उनके प्रबन्ध द्वारा स्वतंत्र रूप से बनाई जाती है। अगस्त, 1992 से फास्फेटिक और पोटेसिक उर्वरकों के नियंत्रणमुक्त के पश्चात उर्वरक कम्पनियां अपनी बिक्री में विपणन तथा उत्पादन सम्बद्ध और अन्य लागतों में मितव्ययता पर जोर के माध्यम से अपनी बिक्री को बढ़ावा दे रही है। जहां तक नियंत्रित उर्वरक यूरिया का संबंध है, प्रतिधारण मूल्य सह आर्थिक सहायता योजना में मानदंडों और वास्तविकों के संयोजन के आधार पर उत्पादन लागतों को मान्यता प्रदान की जाती है और इससे लागतों के यथार्थ मूल्यांकन में सहायता मिलती है। परिवहन लागतों में मितव्ययता लाने के लिए यूरिया के संचालन को भी विनियमित किया जाता है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

Agreement Made by IDPL (RSO, Madras)

3064 PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether the IDPL (RSO, Madras) has entered into an agreement (1989-90) with some firms appointing them as" Institutional Agency" for procurement of orders from the Government/ Semi-quasi Government Institutions and for collection of sale proceeds against the supplies made by the company;

(b) if so, how much commission was paid to those firms;

(c) the reasons for appointing institutional agencies; and

(d) whether the system is continuing or the same has been discontinued?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI EDUARDO FALEIRO); (a) to (d) As reported by IDPL, appointment of Institutional Agents is a prevalent practice in the Pharmaceutical Industry Sector. In terms of the contractual agreements, IDPL has paid a sum of Rs. 129 lakhs to such agents during the period from 1989-90 to 1993-94.

IDPL has reported that it has terminated the said contracts with the agents on the 31st March, 1994 as per the current policy of the company to make supplies to state Government Institutions through authorised distributors of the company, wherever this is permitted by the concerned State Government.

Targets fixed for the production of Urea

3065. SHRI VIRENDRA KATARIA: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) the details of the targets fixed for the production of Urea in Public Undertakings in the year 1994-95;

(b) whether Government have entered into any MoU with them and if so, the details thereof, undertaking-wise; and

(c) what is the total requirement of Urea for the year 1994-95 and the details of total production envisaged?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI EDUARDO FALEIRO): (a) A target of production of 53.73 lakh tonnes of urea has been fixed for the public sector fertilizer companies for the year 1994-95.

(b) Four urea producing public sector undertakings have entered into MoUs with the Government for the year 1994-95. The details of urea/nitrogen production targets agreed to by these companies in the MoU are given below: